एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तृतीया,
मंगलवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

29 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

युवा 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बनें – निधि त्रिपाठी

जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर परिषद ने जलियांवाला बाग की मिट्टी देश के हर स्कूल-कॉलेज में भेजी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन (आगरा कॉलेज मैदान पर 22 से 25 नवम्बर, 2019 तक) में चार प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में राज्य विश्वविद्यालयों के संवर्धन पर जोर दिया गया। मांग की गई कि राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का शैक्षिक कलेंडर एक समान हो। दूसरा प्रस्ताव वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर पारित हुआ। मांग की गई कि एनआरसी पूरे देश में लागू की जाए। तीसरे प्रस्ताव में जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हटाने का स्वागत किया गया। आतंकवाद पीड़ित परिवारों को मदद की मांग की गई। चौथे प्रस्ताव में श्रीराम जन्मभूमि पर सदियों बाद आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सभी समुदायों का अभिनंदन किया गया।

मंगलवार को यूथ हॉस्टल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अ.भा. विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि स्वरोजगार और आर्थिक सुस्ती पर भी बात हुई। आर्थिक जगत के विद्वानों ने सम्मेलन में कहा कि आर्थिक मंदी नहीं, आर्थिक सुस्ती है और पूरे विश्व में है। इससे उबरने के लिए आज का युवा 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बने।

अयोध्या निर्णय के बाद अब 6 दिसम्बर को नहीं मनेगा शौर्य दिवस

अयोध्या पर निर्णय के बाद अब विश्व हिन्दू परिषद ने घोषणा की है कि इस बार 6 दिसंबर को शौर्य दिवस नहीं मनाया जाएगा, उधर केंद्र सरकार ने राम मंदिर के रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मुद्दे पर आए निर्णय के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। संघ इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहता है। इसी कारण इस बार छह दिसंबर को होने वाले शौर्य दिवस को आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। संघ सूत्रों के अनुसार, 'राममंदिर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से आए फैसले के बाद जिस तरह शांतिपूर्वक माहौल रहा है, वैसा ही माहौल आगे बना रहे। इस कारण यह फैसला लिया गया है।' संघ ने इसलिए अपने अनुषांगिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) को अलर्ट कर रखा है। शौर्य दिवस के चक्कर में अति उत्साह में कोई ऐसी घटना न हो जाए, जिसे लेकर एक विवाद खड़ा हो और मंदिर मुद्दा खटाई में पड़ जाए। इसी कारण छह दिसम्बर को होने वाले शौर्य दिवस को नहीं मनाने का फैसला किया गया है। साथ ही संघ चाहता है कि इस मुद्दे पर फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों ने जिस तरह से इसे स्वीकार किया है, इसे देखते हुए कोई अनर्गल बयानबाजी न की जाए। इसी कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पुनर्विचार याचिका पर सभी को बोलने से मना किया गया है। दोनों संगठन चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कहीं कुछ भी ऐसा न हो, जिससे मुस्लिम समाज के दिल में कोई आशंका उत्पन्न हो। इसी कारण वह बहुत सोंच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने आईएएनएस को बताया, 'सर्वोच्च न्यायालय से रामलला के पक्ष में आए निर्णय के बाद अब मंदिर निमार्ण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसीलिए छह दिसम्बर को विहिप के पदाधिकारियों ने शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम को स्थागित कर दिया है।'उन्होंने बताया कि शौर्य दिवस के कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय विहिप पदाधिकारियों ने लेकर देश मे शांति और सद्भाव को बल प्रदान किया है। शमार् ने कहा कि विहिप नही चाहती है कि न्यायालय के इतने बड़े निर्णय को हम दो चार घंटे मे सीमित कर दें। उन्होंने कहा, 'छह दिसंबर की घटना हिन्दुओ को सैदव स्वाभिमान और सम्मान का स्मरण कराती रहेगी।' शर्मा ने बताया कि इस बार विश्व हिंदू परिषद ढांचा ध्वंस की 28वीं बरसी पर छह दिसंबर को शौर्य दिवस के स्थान पर मठ-मंदिरों और घरों में दीप प्रज्वलित करेगी।

मंदिर रख-रखाव के लिए 20.40 करोड़ रुपये

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण की तैयारियों की रुपरेखा बननी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को तीन महीने के भीतर योजना बनाकर पेश करने का निर्देश दिया था। केन्द्र सरकार ने तय किया है कि अयोध्या में मंदिर रखरखाव के लिए 20.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह जानकारी सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश की गई अनुदानों की पहली अनुपूरक मांग में दी गई है।

जिन पाकिस्तानी हिन्दुओं को राजस्थान सरकार ने निकाला उन्हें केन्द्र ने बचाया

हाल ही में राजस्थान सरकार ने वर्षों से भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिन्दुओं को वापस भेजने के आदेश दिए थे, उन्हें केन्द्र सरकार ने भारत की नागरिकता दे दी है।

नई दिल्ली

पाकिस्तान से भारत आए 21 अन्य हिन्दू विस्थापितों को राजस्थान में नागरिकता मिल गयी। जयपुर जिला कलेक्टर ने वर्षों से रह रहे हिन्दू विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की, नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद आंखें छलक उठीं तथा भारत माता की जय का नारा लगाया। ये सभी लोग पाकिस्तान के बिगड़ते हालात और अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर अपनी जान बचाकर यहां आए थे। संभागीय आयुक्त के.सी. वर्मा और जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने भारत गणराज्य की नागरिकता के प्रमाणपत्र सौंपे। दो माह में 35 पाकिस्तानी विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी गई है। 28 अन्य पाकिस्तानी प्रवासियों ने भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा 63 अन्य मामलों में भी जांच हो रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी, जिसमें पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थियों को वापस भेजने की बात कही गई थी। विदेशियों के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी। अशोक गहलोत सरकार ने हिन्दुओं के लिए भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने का आदेश दिया था।

सोनिया करीब 19 साल पहले अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आई थी, आज 19 साल बाद आंखों में फिर से आंसू हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार खुशी के आंसू हैं। पाकिस्तान से आने के पश्चात तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात तो दूर अपना बैंक खाता तक नहीं खोल पा रही थी, लेकिन 19 साल बाद आज नागरिकता को लेकर सरकारी जांच प्रक्रिया समाप्त हो गई और भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र मिल गया।